



मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में क्रियान्वित शासकीय योजनाओं से लाभान्वित जनजाति हितग्राहियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति का अध्ययन

MADHYA PRADESH KE BARWANI JILE ME KRIYANVIT SHASKIY YOJNAON SE LABHANVIT JANJATI HITGRAHIYON KI ARTHIK-SAMIJIK STITHI KA ADHYAN

Jayram Baghel¹ | Prof. N. L. Gupta²

¹ सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)-451551

² प्राध्यापक-वाणिज्य, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)-451551

ABSTRACT

किसी भी देश का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है, जबकि उस देश के प्रत्येक समुदाय का आर्थिक-सामाजिक विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा हो। विकास का आधार यदि असंतुलित होता है, तो देश के सर्वांगीण विकास की अवधारणा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। भारत जैसे विकासशील देश में जनजाति विकास की ओर भी सरकार का विशेष ध्यान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.61 प्रतिशत है और देश के क्षेत्रफल के लगभग 15 प्रतिशत भाग पर जनजातीय वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन यह वास्तविकता है कि जनजातीय वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान की जरूरत है, जिससे कि उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ाया जा सके।

KEYWORDS: [olxhkfo d k] t ut kfr] vl a6yr

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान में देश की अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हित और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत देश की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में नियोजित विकास के आधार पर जनजातीय विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने इनके विकास की ओर कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना और बाकी है। देश में जनजाति समाज के विकास विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से देश के आदिवासी समाज के लोगों का विकास करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। सरकार इस समाज के परिवारों के विकास के लिए अनेक विकासमूलक योजनाएँ संचालित कर रही है। जिसके अन्तर्गत जनजातीय समुदाय का विकास हो सके।

1. शोध समस्या का चयन:

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए मध्यप्रदेश के जनजाति बाहुल्य बड़वानी जिले का चयन किया गया है। बड़वानी जिले में जनजाति विकास से संबंधित अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लेकिन शोध कार्य की आवश्यकता एवं समय-सीमा को ध्यान में रखकर कुल 05 महत्वपूर्ण योजनाओं को इस शोध कार्य का आधार मानकर उनका विश्लेषण किया गया है। बड़वानी जिले में संचालित चयनित योजनाओं का उचित लाभ जनजातीय वर्ग के लोगों को मिल रहा है या नहीं? इन योजनाओं का अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक-सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा चयनित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता का उद्देश्यों के अनुरूप उपयोग किया जा रहा है या नहीं? क्या संबंधित शासकीय योजनाएँ अपने उद्देश्यों में सफल हो रही है या नहीं? क्या भविष्य में भी इन शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए या नहीं? इन समस्याओं को आधार मानकर ही शोधार्थी द्वारा "मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में क्रियान्वित शासकीय योजनाओं से लाभान्वित जनजाति हितग्राहियों का आर्थिक अध्ययन" नामक शोध विषय का चयन किया गया है। इस शोध कार्य के तहत मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले संचालित एवं अध्ययन के लिए चयनित योजनाओं से लाभान्वित अनुसूचित जनजाति के परिवारों के उन सदस्यों को शामिल किया गया है, जो योजनाओं के हितग्राही हैं।

2 अध्ययन के उद्देश्य:

इस शोध कार्य के लिए चयनित शोध विषय के विश्लेषण के निर्धारित उद्देश्य निम्नानुसार हैं—

1. शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के बदलते आर्थिक स्वरूप का अध्ययन करना।
2. जनजाति हितग्राहियों के जीवन पर चयनित शासकीय योजनाओं के आर्थिक-सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना।

3. अध्ययन का महत्व:

भारत के संविधान में उल्लेखित है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के हितों की रक्षा

करना एवं उनके आर्थिक-सामाजिक को दिशा प्रदान करना एक कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है। "मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में क्रियान्वित शासकीय योजनाओं से लाभान्वित जनजाति हितग्राहियों का आर्थिक अध्ययन" नामक शोध विषय के चयन करने का महत्व यह है कि इस महत्वपूर्ण शोध कार्य के माध्यम से मध्य प्रदेश के जनजाति अधिसंख्य बड़वानी जिले में जनजाति के विकास के लिए क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी एवं उनके हितग्राहियों को लाभ की स्थिति पता चल सकेगा।

4. अध्ययन का क्षेत्र:

इस शोध कार्य के लिए अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का चयन किया गया है।

5. निदर्शन प्रक्रिया:

अनुसूचित जनजातियों के विकास की योजनाओं के आर्थिक अध्ययन से संबंधित इस शोध कार्य की समुचित शोध प्रक्रिया के लिए जो निदर्शन प्रक्रिया अपनाई गई है, वह इस प्रकार है—

6 अध्ययन के समग्र:

इस शोध अध्ययन के समग्र के रूप में अध्ययन हेतु चयनित बड़वानी जिले उन जनजाति परिवारों को शामिल किया गया है, जो चयनित योजनाओं के समस्त हितग्राही हैं।

7. अध्ययन की इकाई:

अध्ययन के समग्र में से अध्ययन की इकाई के रूप में बड़वानी जिले की चयनित योजनाओं के समस्त हितग्राहियों में से कुल 405 हितग्राहियों को सम्मिलित किया गया है।

8. उत्तरदाताओं का चयन:

इस महत्वपूर्ण शोध कार्य की पूर्ति के लिए हितग्राही उत्तरदाताओं का चयन शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सोद्देश्य प्रतिचयन विधि से किया गया है। बड़वानी जिले की 9 तहसीलों से चयनित योजनाओं के कुल 450 लाभान्वित हितग्राहियों का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया है।¹ उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए बड़वानी जिले की प्रत्येक तहसील से 3 गाँवों का चयन किया गया है। इस प्रकार से जिले के कुल 27 (3 x 9) गाँवों का चयन किया गया है। गाँवों के चयन के बाद प्रत्येक गाँव से 15 हितग्राहियों का चयन शोध कार्य के उत्तरदाताओं के रूप में किया गया है। (15 हितग्राहियों के चयन के समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि अध्ययन हेतु चयनित कुल 05 योजनाओं में से प्रत्येक योजना के 03 हितग्राहियों का चयन हो सके।) इस प्रकार जिले के कुल 27 गाँवों से 405 उत्तरदाताओं (27 x 15) का चयन अध्ययन की इकाई के रूप में किया गया है।

9. आँकड़ों का संकलन:

इस शोध कार्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का

संकलन किया गया है।

अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं—

1. अध्ययन क्षेत्र के चयनित कुल उत्तरदाताओं में से 44.70 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित हैं और शेष 55.30 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित हैं। इस प्रकार उक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं में से सबसे अधिक उत्तरदाता अशिक्षित हैं।
2. अध्ययन क्षेत्र के जो शिक्षित उत्तरदाताओं हैं, उनमें से 39.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं की शिक्षा प्राथमिक स्तर तक की है, वहीं 30.94 प्रतिशत उत्तरदाताओं की शिक्षा माध्यमिक स्तर तक की है तथा 23.76 प्रतिशत उत्तरदाता हाई स्कूल/ हा. से. तक शिक्षित हैं। शेष 6.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महाविद्यालयीन स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के शिक्षित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक उत्तरदाता केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त हैं।
3. अध्ययन हेतु चयनित कुल उत्तरदाताओं में से 26.91 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार संयुक्त परिवार प्रणाली का है, जबकि 73.09 प्रतिशत उत्तरदाताओं का परिवार एकाकी परिवार प्रणाली में रहते हैं। इस प्रकार विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों में सर्वाधिक लोग अब एकल परिवार प्रणाली निवास करते हैं।
4. अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 13.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में -3 सदस्य हैं तथा 37.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में कुल सदस्यों संख्या 4-6 के मध्य है, वहीं 27.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में 6-9 सदस्य हैं। 20.99 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में 9 से अधिक सदस्य हैं। इस प्रकार उक्त आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक उत्तरदाताओं के परिवार में 4 से अधिक सदस्य हैं।
5. अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 87.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर/मकान का स्वरूप कच्चा है एवं 8.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं का घर/मकान अर्द्ध पक्का है, जबकि 3.21 प्रतिशत उत्तरदाताओं का घर/मकान पक्का है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाताओं के घर/मकान कच्चे हैं।
6. चयनित कुल उत्तरदाताओं में से 70.13 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहाँ पानी का स्रोत हैंडपंप है और 11.85 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहाँ पानी का स्रोत के रूप में नल व्यवस्था है, जबकि 13.58 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहाँ कुएँ तथा 4.44 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहाँ अन्य व्यवस्था के रूप में पानी के स्रोत हैं। इस प्रकार सर्वाधिक उत्तरदाताओं के लिए हैंडपंप ही पानी के स्रोत के रूप में है।
7. अध्ययन क्षेत्र के चयनित कुल उत्तरदाताओं में से 82.96 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि कृषि कार्य करते हैं और 15.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा मजदूरी की जाती है, जबकि 1.48 प्रतिशत उत्तरदाता व्यवसाय में संलग्न हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि चयनित उत्तरदाताओं में सर्वाधिक उत्तरदाता कृषि कार्य करते हैं।
8. अध्ययन क्षेत्र के जिन उत्तरदाताओं के पास कृषि भूमि है, उनमें से 45.24 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 2 एकड़ से कम कृषि है और 28.27 प्रतिशत उत्तरदाताओं की 2-4 एकड़ कृषि है, वहीं शेष 26.49 प्रतिशत उत्तरदाताओं की कृषि भूमि 4 एकड़ से अधिक है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं की कृषि भूमि 4 एकड़ तक है।
9. अध्ययन क्षेत्र के जिन उत्तरदाताओं के पास कृषि भूमि है, उनमें से 77.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं की कृषि भूमि असिंचित है और 22.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं की कृषि सिंचित है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के ज्यादातर उत्तरदाता ऐसे हैं जिनकी कृषि भूमि असिंचित है।
10. अध्ययन क्षेत्र के चयनित कुल उत्तरदाताओं में से 8.39 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार का मात्र 1 सदस्य आर्थिक कार्य करता है, जबकि 31.11 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार के 2 सदस्य और 38.76 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार के 3 सदस्य आर्थिक कार्यों में संलग्न हैं। बाकि 21.74 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार के 4 या 4 से अधिक सदस्य आर्थिक कार्य करते हैं। अतः उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदाता ऐसे हैं, जिनके परिवार के 3 सदस्य आर्थिक कार्य करते हैं।

उपसंहार:

इस प्रकार शोध अध्ययन के उक्त निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभांशित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में अन्य वर्गों की तुलना में बहुत विचलन देखने का मिलता है।

संदर्भ:

1. भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश श्रृंखला-24
2. शुक्ल,एस.एम.,सहाय,एस.पी. (2005) सांख्यिकीय के सिद्धांत, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा (उ.प्र.)